को०इं०लि० में न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वेतन सभी भत्तों सहित 3638.70 रु० प्रति माह है।

(ग) कोल इंडिया में महिला कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार किए जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए है:—

(1) महिलाओं की सेवाओं को अधिक लाभदायक रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण/पुर्न-प्रशिक्षण दिया जाता है।

(i) सुरक्षा तथा रखवाली का कार्य।

(ii) कार्यशालाओं में आर्मेचर वाइडिंग।

(iii) टोकरी बनाना।

(iv) कार्यालय चपरासी।

(v) विभिन्न मशीनों के प्रचालकों के रूप में नियोजन।

(vi) हाउस कीपिंग कार्य तथा

(vii) सिलाई तथा दर्जी का कार्य।

(2) भा०को०को० लि० तथा से०को०लि० में सुरक्षा गार्डों के रूप में कई महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न खुदाई/खनन मशीनों के प्रचालकों के रूप में नियोजित किए जाने हेतु कई महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ महिला कर्मचारियों को मैकेनिक हैल्पर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पूर्व में महिला कर्मचारियों को केवल गैर कार्य-कौशल वाले कार्यों जैसे वैगन लदान, शेल चुनना तथा कुछ मामलों में खदान भराई कर्ता के रूप में ही नियोजित किया जाता था।

(3) महिला कर्मचारियों की बहुत सी श्रेणियों को यूनिफार्म उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों की सेवाओं को विभिन्न अन्य कार्यों जैसे कार्यालय तथा लिपिकीय कार्यों, कम्प्यूटर, अर्द्ध-चिकित्सकीय एवं पुस्तकालय आदि के कार्यों में भी उपयोग किया जा रहा है।

Committee for Solving Problems of Subsidence and Fire in Raniganj and Jharia

467. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether a Committee was constituted with Secretary Coal as Chairman to solve the problem of subsidence and fire in Raniganj and Jharia Coal fields in a comprehensive manner;

(b) whether the Committee was to submit its report in June, 1997;

(c) if so, the recommendations of the Committee;

(d) if not, the reasons for delay in submission of the report; and

(e) the interim action plan of Government on the problem of subsidence and fire?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The recommendations of the Interim Report made by the High Level Committee in June, 1996 are as under:—

Where ever possible settlements of all unstable areas should be shifted to non-coal bearing zones. For this purpose, satellite townships are the best longterm solution against subsidence hazards in the coalfields.

The mitigation measures against subsidence and fire hazards are very costly options and fruitful implementation of these measures can only be possible through separate executing agency with separate funding. Formulation and representatives of such agencies responsible for formulating schemes, their implementation and management of funds should be finalised before the final report is submitted.

For tackling the problems of fire and subsidence both in Jharia coalfield and Raniganj coalfield, the participation and assistance from State Government and local administration is essential. Any enforcing agency entrusted with the responsibilities of carrifying out mitigating measures against fire and subsidence in Raniganj coalfield and Jharia coalfield should be adequately represented by the above authorities.

The innovative hydro-pneumatic stowing technology currently being used at some locations in Raniganj coalfield has been found to be very slow process. High pressure slurry pumping technology for underground void filling should be tried at some locations in Bharat Coking Coal Limited for stabilising inaccessible unstable underground workings.

Intensive stabilisation work of unstable areas under locations, like Raniganj town from where population can not be shifted, should be carried out and persons affected in the high risk but low density areas may be relocated in a phased manner.

The mitigation measures against subsidence and fire hazards are very costly options. For arranging fund for the purpose of stabilisation of subsidence prone areas and resettlement of affected people, the current limit of excise duty levied for Coal Conservation and Development Act fund of Rs. 10 per tonne may be increased to Rs. 25 per tonne.

The Interim Reports submitted by Bharat Coking Coal Limited and Eastern Coalfields Limited jointly with State authorities on the fire and subsidence prone areas indicating likely affected population and financial implications should be kept in view while drawing up priority-wise schemes for immediate and effective way to deal with the problems.

(e) Considering the urgency one scheme each by Eastern Coalfields Limited and Bharat Coking Coal Limited for shifting of population from the unsafe areas has been decided to be taken up without waiting for the positioning of the institutional arrangement from plan funds available with Ministry of Coal. The final report with above and other slight modifications in the Interim Report is under submission.

उड़ीसा के वसुन्धरा कोयला खदानों में उपलब्ध कोयला

468. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला स्थित गोपालपुर के वसुन्धरा कोयला खानों में उपलब्ध कोयला किस श्रेणी का है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त कोयला खानों से कोयला उठाने के लिए कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन खानों के कोयले के निर्यात के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पता लगाए गए प्रमुख उपभोक्ता कौन से हैं अथवा खानों के कोयले के निपटान के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के गोपालपुर ब्लॉक की वसुन्धरा कोयला खान में उपलब्ध कोयला "ई" तथा "एफ" ग्रेड के हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 हेतु इस खान से प्रेषण का लक्ष्य 4.8 लाख टन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) इन खानों से कोयला प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के नाम निम्नलिखित हैं:— (i) हीराकुंड पावर कारपोरेशन लि॰ (ii) उड़ीसा सीमेंट लि॰ (iii) आई॰डी॰सी॰ओ॰एल॰ सीमेंट इत्यादि। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत खानों से भी विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कोयला प्राप्त किया जा रहा है। को॰ई॰ लि॰ से प्राप्त सूचना के अनुसार, बुन्डामल झारसुग्डा में रेलवे साइडिंग जनवरी, 1998 से कार्य करना आरंभ कर देगी, जहां से इस खान का कोयला अन्य उपभोक्ताओं को प्रेषित किया जा सकेगा।